The monthly newsletter of Bihar Foundation

BIHAR FOUNDATION
BONDING·BRANDING·BUSINESS

जनवरी 2018

बिहार

The land of enlightenment

राष्ट्रपति के कर–कमलों द्वारा राजगीर में चौथा अंतरराष्ट्रीय धर्म–धम्म सम्मेलन का उद्घाटन

माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 11 जनवरी, 2018 को बिहार के राजगीर में चौथा अंतर्राष्ट्रीय धर्म–धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा इंडिया फाउंडेशन के सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रिलिजन एंड सोसाइटी एवं विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। सम्मेलन का आयोजन देश और विदेश के शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर ला कर एक बेहतर समाज और दुनिया के निर्माण के लिए दशा–दिशा तय करने और विचारों को साझा करने के उद्देश्य से किया गया था। सम्मेलन को संबोधित करते हुए माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि बौद्ध धर्म ने बहुलवाद और विचारों की विविधता को बढ़ावा दिया है।

इस तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन समारोह धर्म–धम्म परंपराओं में राज्य और सामाजिक व्यवस्था विषय पर आधारित था। उद्घाटन समारोह में बिहार के माननीय राज्यपाल सत्यपाल मलिक और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और श्रीलंका के विदेश मंत्री तिलक मारापना भी शामिल हुए।

तीन दिवसीय सम्मेलन में 11 देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की और करीब 60 शोधपत्र प्रस्तुत किए गए। सम्मेलन में आये प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए श्री नीतीश कुमार ने नालंदा विश्वविद्यालय में एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्थापना की बात कही साथ ही इसके लिए भूमि उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया।

****

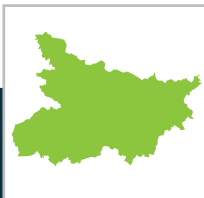

Get in touch
Tel. +91-612-2547371
email:info@biharfoundation.in
Web: http:ËËwww.biharfoundation.in

Contents

01 राष्ट्रपति के कर–कमलों द्वारा राजगीर में चौथा अंतरराष्ट्रीय धर्म–धम्म सम्मेलन का उद्घाटन

04 राज्य में 13 जिलों के किसान अब अपने उत्पादों को ई-रकम केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन बेच सकेंगे

04 दहेज और बालविवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बनाई गई राज्यव्यापी मानव श्रृंखला

04 अब दरभंगा से भी उड़ान भरेगा हवाई जहाज

05 दिल्ली-पटना एक्सप्रेसवे के लिए जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

05 50 किलोमीटर की दूरी तक गंगा नदी में सुल्तानगंज से कहलगांव तक होगा नौका विहार

05 नए स्टार्ट अप को मदद देगी बिहार सरकार

06 राज्य में किसानों के लिए बनेगी नयी कृषि-वानिकी नीति

06 सरकार मोइनुलहक स्टेडियम को विकसित करने के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के साथ करेगी समझौता

07 बिहार को मिला कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड

07 बिहार के लोक गायिका शारदा सिन्हा पद्म भूषण एवं वैज्ञानिक मानस वर्मा पद्मश्री से सम्मानित

08 जनवरी महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठकों में लिए गए कुछ अहम फैसले

एक अरसे से बिहार फाउण्डेशन से जुड़े तमाम लोगों की इच्छा थी कि एक ऐसा मासिक न्यूज़लेटर निकले, जो बिहार में चल रहे उस माह की सकारात्मक गतिविधियों का एक तथ्यात्मक लेखा–जोखा हो।

एक ऐसा लेखा–जोखा जो उन्हें बिहार की सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक मुख्यधारा में भावनात्मक ढ़ंग से जुड़ने में एक दिशा प्रदान करे। अब से हर माह प्रकाशित होने वाला यह न्यूज़लेटर उसी दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है।

अपनी माटी और धरोहर से जुड़े रहने की इच्छा किसी भी प्रवासी के लिए सहज़ है। मुख्यधारा–मीडिया अपनी चारित्रिक विशेषताओं के कारण प्रवासी बिहारियों को उन बिन्दुओं से लगातार साक्षात्कार कराने मे असक्षम है, जिसे जानकर वह और गौरवान्वित महसूस करें।

जबकि हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने बिहार में हो रहे ऐसे प्रयासों की कमी नहीं। कमी है केवल उन्हें संजोने की। बिहार फाउण्डेशन ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह कदम करीब दो वर्ष पहले उठाया था। उसी दिशा में उठाया गया यह दूसरा महत्वपूर्ण कदम है।

यह न्यूजलेटर उन प्रवासियों को आपस में, उन्हें उनकी माटी से, और बिहार में बह रही सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने में मदद करेगी। आशा है ऐसे यह प्रयास उन सबको बिहार का ब्रांड एम्बैसेडर बनाने में मददगार साबित करेगा।

डॉ एस सिद्धार्थ, आईएएस
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार फाउण्डेशन

राज्य में 13 जिलों के किसान अब अपने उत्पादों को ई–रकम केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन बेच सकेंगे

राज्य में 13 जिलों के किसान अब अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकेंगे। किसानों के उत्पाद को बेचने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत होने जा रही है। इसका नाम ई–रकम (राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी) रखा गया है। इसके लिए केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय और जीविका के साथ समझौता हुआ है। राज्य में मक्के की खरीदारी से इसकी शुरुआत हो रही है । बाद में सभी फसलों को ई–रकम सेंटर के माध्यम से बेचा जाएगा। ई–रकम सभी किसान उत्पादक संगठन वाले जिलों में खोले जाएंगे।

ई–रकम के जरिए किसान अपने उत्पाद सीधे बेच सकेंगे। ऐसे में बिचौलिये व कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा। ई–रकम यानी ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी एक डिजिटल पहल है जो किसान, एफपीओ, पीएसयू नागरिक आपूर्ति और खरीदार यानी आम लोगों, व्यापारियों और फूड प्रोसेसर आदि को एक साथ एक मंच पर लाकर कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीदारी प्रक्रिया को आसान बनाती है। योजना के पहले चरण में राज्य के 13 जिलें पटना, नालंदा, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, किशनगंज, जमुई और कटिहार में खुलेंगे केंद्र।

****

दहेज और बालविवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बनाई गई राज्यव्यापी मानव श्रृंखला

बाल–विवाह और दहेज जैसे सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राज्य सरकार के अभियान के अंतर्गत लगभग 14,000 किलोमीटर लंबी राज्यव्यापी मानवीय श्रृंखला बनाई गई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐतिहासिक गांधी मैदान से उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के उपस्थिति में मानव श्रृंखला की शुरुआत की।

पिछले वर्ष की दो करोड़ लोगों की सहभागिता से बने 11,292 किलोमीटर की बने मानव श्रृंखला के तुलना में इस साल करीब चार करोड़ लोगों की भागीदारी से 13,660 किमी मानव श्रृंखला बनाई गई। कार्यक्रम में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान समर्थित नारे से सजे गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। मुख्यमंत्री ने गुब्बारे उड़ाकर बाल विवाह एवं दहेज को 'ना' कहने की अपील की। प्रतिभागियों श्रृंखला में दहेज और बाल विवाह के खिलाफ बड़े–बड़े बैनर के साथ खड़े हुए। यह मानव श्रृंखला, नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, जिला, प्रखंड, पंचायत, गांवों की विभिन्न सड़कों और पगडंडियों से होकर गुजरी जिसमे लगभग 4.5 करोड़ लोगों शामिल हुए।

****

अब दरभंगा से भी उड़ान भरेगा हवाई जहाज

बिहार के सबसे लंबे रनवे दरभंगा से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। दरभंगा का एयर फोर्स का यह रनवे 9000 फुट लंबा है जिसे तीन हजार फुट का और विस्तार दिया जाना है। अगले छह महीने के अंदर दरभंगा से हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। दो विमानन कंपनियों स्पाइस जेट और इंडिगो ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत दरभंगा से मुंबई, बेंगलुरू और दिल्ली की सेवा के लिए निविदा डाली है। विमान सेवा शुरू करने के पहले सरकार दरभंगा में एयर फोर्स एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन का निर्माण करेगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर हवाई सेवा की शुरुआत के लिए एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया और डीजीसीए की चार सदस्यीय टीम ने नवंबर 2017 में दरभंगा का दौरा किया था। केंद्रीय उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट के विकास लिए 100 करोड़ केंद्र सरकार खर्च करेगी। उड़ान के तहत विमानन कंपनियों ने दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बंगलौर के लिए हवाई सेवा का प्रस्ताव दिया

है। दरभंगा स्थिति हवाई अड्डा एयरबस 320 और बोइंग 737 जैसे विमान लैंड करने के लिए उपयुक्त है।

दरभंगा से विमान सेवा शुरू करने के साथ–साथ पटना एयरपोर्ट का विस्तार भी किया जायेगा। जल्द ही बिहटा एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित 108 एकड़ जमीन एयरपोर्ट ऑथोरिटी को सौंपी जाएगी। पटना एयरपोर्ट पर बनने वाले 803 करोड़ की लागत से 45 लाख यात्रियों की क्षमता वाले नए टर्मिनल के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट और डिजायन की स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही पूर्णिया में भी वर्ष के अंत तक आईएएफ द्वारा नियंत्रित हवाई पट्टी को वाणिज्यिक उड़ानों के लिए खोला जायेगा।

****

दिल्ली–पटना एक्सप्रेसवे के लिए जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बीच राज्य के विभिन्न सड़क परियोजना को जल्दी निपटारे और गंगा के जीर्णोद्धार के मुद्दे पर पिछले महीने बैठक हुई। मीटिंग में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी सड़क परियोजना को निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने एवं उत्तर बिहार के जीवन रेखा कही जाने वाली महात्मा गांधी पुल के पुनर्निर्माण कार्य को गति देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया।

मीटिंग में दिल्ली–पटना एक्सप्रेसवे के निर्माण के बारे में भी चर्चा हुई। नितिन गडकरी ने दिल्ली–पटना एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर बनाने की सलाह दी। इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के बाद पटना से दिल्ली तक का अनुमानित समय मात्र 11 घंटे का हो जायेगा। इसके साथ ही भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समांतर गंगा पर एक नया पुल के प्रस्ताव के साथ साथ पटना रिंग रोड परियोजना पर भी चर्चा हुई।

****

50 किलोमीटर की दूरी तक गंगा नदी में सुल्तानगंज से कहलगांव तक होगा नौका विहार

राज्य में इको–टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन एवं पर्यावरण विभाग ने सुल्तानगंज से कहलगांव तक लगभग 50 किलोमीटर की दुरी तक गंगा में नौका विहार कराएगा। इसके लिए 15 लाख की लागत से 25 सीटों वाली मोटर बोट खरीदी जा चुकी है। मार्च के अंत तक डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र में इको टूरिज्म शुरू हो जाएगा।

15 लाख की इस बोट में 25 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। मार्च के अंत तक नौका विहार शुरू करा दिया जाएगा । लोग मोटर बोट के सहारे जलीय जीव डॉल्फिन सहित प्रवासी पक्षियों को सहजता से न सिर्फ देख पाएंगे, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में उनके योगदान को भी जान पाएंगे। कुदरत की गोद में 50 किलोमीटर का यह सफर पर्यटन को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। लोगों को जलीय जीव एवं प्रवासी पक्षियों की जानकारी देने के लिए पर्यावरणविद् को भी लगाया जाएगा।

****

नए स्टार्ट अप को मदद देगी बिहार सरकार

बिहार में अब नए स्टार्ट–अप करने वालों को सरकार करेगी मदद। सरकार का यह फैसला खास तौर पर आईटी, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, परिधान और चमड़ा उद्योग चलाने वाले कारोबारियों को फायदा होगा। इसके साथ ही जीएसटी वापसी, ईपीएफ और ईएसआई मद में दी जानी वाली राशि में भी मदद की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार इन स्टार्ट अप के तहत दिए जाने वाली नौकरी पर प्रति व्यक्ति 20 हजार रुपये की कौशल विकास अनुदान उपलब्ध कराएगी।

इसके जरिए करीब 5 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होगा। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए 2016–17 में पूंजी उद्यम कोष के लिए बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट को 50 करोड़ उपलब्ध कराया गया है। स्टार्टअप के लिए ऑनलाइन मिले 3,751 प्रस्ताव में से 22 को प्रथम किस्त के रूप में 55 लाख दिया जा चुका है।

****

राज्य में किसानों के लिए बनेगी नयी कृषि–वानिकी नीति

देश में पहली बार भागलपुर टिश्यू कल्चर लैब में बांस के डेढ़ लाख पौधे तैयार किए गए हैं। शीघ्र ही सुपौल में भी बांस का टिश्यू कल्चर लैब स्थापित कर किसानों के लिए 'हरा सोना' साबित हो रहे बांस की खेती को बढ़ावा दिया जायेगा। मुंगेर में कृषि–वानिकी कॉलेज स्थापित करने के साथ ही औषधीय व सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय को दोगुना किया जायेगा।

बिहार में दूसरे कृषि रोड मैप (2012–17) के तहत प्रथम कृषि–वानिकी योजना प्रारंभ हुई जिसके अन्तर्गत 6 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य था मगर 70 हजार से ज्यादा किसानों के सहयोग से 6 करोड़ 13 लाख पौधों का रोपण किया गया। तीसरे कृषि रोड मैप (2017–22) के दौरान कृषि–वानिकी के तहत 5.30 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य है जिसमें 3.80 करोड़ सामान्य प्रजाति के व 1.5 करोड़ पाप्लर प्रजाति के पौधे होंगे। कम अवधि में तैयार होने वाले पौधों बांस, पाप्लर, गम्हार, सेमल, कदम्ब, सहतूत और अर्जुन आदि के रोपण के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जायेगा। एक अनुमान के अनुसार 2018–19 में 27 लाख क्यूसेक लकड़ी तैयार होगी जबकि 2019–20 में 1 करोड़ 78 लाख क्यूसेक और उसके अगले साल 5 करोड़ क्यूसेक लकड़ी उपलब्ध होगी।

****

सरकार मोइनुलहक स्टेडियम को विकसित करने के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के साथ करेगी समझौता

राज्य सरकार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के साथ एक समझौता करेगी जिसके तहत मोइनुलहक स्टेडियम को संवारा और विकसित किया जायेगा। यह घोषणा उपमुख्यमंत्री द्वारा चार दिवसीय बिहार एकलव्य खेल के शुभारंभ समारोह में की गई। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, पटना में नौ से 12 जनवरी तक चलने वाली खेल प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए उन्होंने सूचित किया कि हाल में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 17 साल के बाद बिहार की टीम भी रणजी क्रिकेट में भाग ले सकेगी।

इस स्टेडियम में बिहार के लड़के उच्चस्तरीय क्रिकेट का प्रशिक्षण ले सकेंगे। बिहार में 22 एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र संचालित कर 370 बच्चे प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। अगले वर्ष 17 और एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र खोल कर एक हजार बच्चों को नामांकित करने का सरकार का लक्ष्य है। प्रशिक्षण केंद्र के बच्चों के खाने की राशि प्रतिदिन 100 रुपये से बढ़ा कर 225 रुपये, एक बार की जगह दो बार खेल किट और ड्रेस के साथ ही प्रशिक्षकों के मानदेय को 8 हजार से बढ़ा कर 30 हजार कर दिया गया है। राजगीर में सरकार की पहल पर 633 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स सह स्टेडियम के निर्माण के लिए 90 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है।

________________****____________________

बिहार को मिला कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को 'कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड' मिला है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम (बीपीजीआरए) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सोसाइटी की ओर से अपर मिशन निदेशक डॉ प्रतिमा ने को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह पुरस्कार दिया गया।

डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर, नयी दिल्ली, द्वारा स्थापित यह पुरस्कार प्रशासन में इनोवेशन के लिए दिया जाता है। देश में अपनी तरह का पहला बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को 2015 में पेश किया गया ताकि नागरिकों को उनकी शिकायतों की सुनवाई और निवारण के लिए कानूनी अधिकार मिल सके। इसके लागु होने के बाद से इस अधिनियम से लाखों नागरिकों जिनके मामले काफी दिनों से लंबित थे लाभान्वित हुए हैं। अधिनियम इस मामले में भी देश में पहला है कि यह सुनिश्चित करता है कि हर शिकायत के एक निष्पक्ष प्राधिकरण हो तथा प्राधिकरण नागरिकों के साथ–साथ सरकारी अधिकारीयों के साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित करता है।

________________****____________________

बिहार के लोक गायिका शारदा सिन्हा पद्म भूषण एवं वैज्ञानिक मानस वर्मा पद्मश्री से सम्मानित

भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों में बिहार के दों हस्ती को उनके असाधारण उपलब्धियों के लिए चुना गया है। मशहूर गायिका शारदा सिन्हा को पद्मभूषण और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा को पद्मश्री के लिए चुना गया है। दरभंगा के रहने वाले मानस बिहारी वर्मा इसरो की तेजस परियोजना से जुड़े रहे हैं।

स्वर कोकिला से लेकर पद्मश्री तक का सम्मान पा चुकीं बिहार की शारदा सिन्हा ने छठ गीतों को एक अलग पहचान दी है। लोक आस्था के महापर्व छठ के गीतों में शारदा सिन्हा के गीतों का एक अलग पहचान मिली है। तेजस विमान की नींव रखने वाले वैज्ञानिकों में एक डॉ मानस बिहारी वर्मा पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोगी रहे हैं।

________________****____________________

जनवरी महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठकों में लिए गए कुछ अहम फैसले

- वित्तीय वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अनुमोदित मॉडल स्कूल के स्थापना के क्रम में 81 मॉडल विद्यालयों के अधूरे भवन निर्माण एवं भवन निर्माण को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017 -2018 में विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति।
- माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु सभी पंचायतों में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना सम्बन्धी निति के अंतर्गत भूमि की न्यूनतम उपलब्धता 0.75 एकड़ करने एवं इस नीतिगत निर्णय से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं अन्य योजना के तहत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय (2) में उत्क्रमण करने की स्वीकृति।
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 02 (ओरंगाबाद बरबडडा) के 6 लेनिंग परियोजना हेतु औरंगाबाद जिला अंतर्गत विभिन्न अंचल में भूमि यथास्थिति में भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति।
- लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अंतर्गत "बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना" के क्रियान्वन हेतु कार्यान्वन अनुदेश संशोधित करने की स्वीकृति।
- स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बोधगया में कल्चरल सेण्टर के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृत प्रदान करते हुए भवन निर्माण विभाग को योजना के कार्यकारी एजेंसी नामित करने की स्वीकृति।
- पटना में प्रस्तावित डॉ. ए. पी. जे. कलाम साइंस सिटी के लिए Architect, Content Design, Exhibit Design, एवं Project Management हेतु परामर्शी समूह का चयन परामर्शी शुल्क की प्रशासनिक स्वीकृति।
- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत उठाव किये गए खाद्दान के अवशेष अंश की वसूली एवं उसके क्षति के लिए दायित्व के निर्धारण हेतु गठित न्यायिक जाँच कमिटी के कार्यकाल को छह माह बढ़ाने की स्वीकृति।
- समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चें, गर्भवती माताओं एवं अतिकुपोषित बच्चों को दी जाने वाली पूरक पोषाहार की राशि को तत्काल प्रभाव से बढाकर क्रमशः 8 रूपये, 9.50 तथा 12 रूपये प्रतिदिन करने की स्वीकृति।
- किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के अनतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली पोषाहार की राशि बढाकर 9.50 प्रतिदिन करने एवं वर्तमान के 12 जिलों के स्थान पर तत्काल प्रभाव से पुरे राज्य में लागु करने की स्वीकृती।
- आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में 'Centre for Geographical Studies' की स्थापना एवं संचालन हेतु निदेशक एवं समन्वयकों के पदों का सृजन तथा विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित तीन शैक्षणिक केन्द्रों 'School of Journalism and Mass Communication', 'Patliputra School of Economics', एवं 'Centre for River Studies' और प्रस्तावित Centre for Geographical Studies के लिए निदेशक पद नियुक्ति हेतु सर्च कमेटी के गठन एवं निदेशक के वेतन सम्बन्धी प्रस्ताव पर स्वीकृति।

www.sauvcommunications.com

Bihar Foundation
Head Office: 6th Floor, Indira Bhawan, RCS Path, Patna, Bihar (INDIA).
Phone: +91-612-2547371
Email: General: info@biharfoundation.in
Helpdesk: helpdesk@biharfoundation.in